बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मासिक प्रतिवेदन

फरवरी, 2024

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

विषय सूची

पेज नं.

(A)	समुदाय स्तर पर सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के क्रियान्वयन, लू एवं वज्रपात से बचाव संबंधी मार्गदर्शिका के संबंध में बैठक	03
(B)	वज्रपात से बचाव की कार्ययोजना के क्रियान्वयन पर बैठक आयोजित	05
(C)	सामुदायिक स्वयंसेवकों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण का प्रशिक्षण	07
(D)	बालासोर दुर्घटना : पीड़ितों के पुनर्वास व पुनर्प्राप्ति का समन्वित प्रयास	08
(E)	डीआरआर रोडमैप अद्यतीकरण	09
(F)	स्वास्थ्य कर्मियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	11
(G)	आपदाओं से बचाव हेतु जिलों में तैयार हो रही मॉकड्रिल टीम	12
(H)	बीएसडीआरएन एप के व्यापक इस्तेमाल हेतु जिलों में बैठक	13
(I)	शहरों में जल जमाव की समस्या से निपटने पर विमर्श	14
(J)	O2B2 संस्था प्राधिकरण के साथ मिलकर करेगी काम	15
(K)	कैंसर रोग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने स्वस्थ रहने के बताए गुर	16
(L)	साइन लैंग्वेज वर्कशॉप का आयोजन	18
(M)	फरवरी माह में मीडिया में प्राधिकरण की गतिविधियों की कवरेज	19
(N)	अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम	20
(O)	फरवरी माह की व्यय विवरणी (रुपये में)	21
(P)	जन–जागरूकता के लिए मास मैसेजिंग	22

(A) समुदाय स्तर पर सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के क्रियान्वयन, लू एवं वज्रपात से बचाव संबंधी मार्गदर्शिका के संबंध में बैठक

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सभागार में दिनांक 23 फरवरी, 2024 को समुदाय स्तर पर सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के क्रियान्वयन, लू एवं वज्रपात बचाव संबंधी मार्गदर्शिका के संबंध में प्रस्तुतिकरण एवं परिचर्चा हेतु विभिन्न हितधारकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक माननीय डॉ. उदय कांत, माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में तथा माननीय सदस्य श्री पी. एन. राय की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुई। इस बैठक में विभिन्न जिलों से अपर समाहर्ता / प्रभारी, आपदा प्रबंधन, सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर्स ने भाग लिया । उक्त बैठक में जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में होने वाली वृद्धि/लू की चरम परिस्थितियों तथा वज्रपात से बचाव हेतु समुदाय स्तर पर जन जागरूकता तथा समय पूर्व तैयारी हेतु सभी हितधारकों को साथ मिलकर कार्य किए जाने के संबध में विस्तारपूर्वक प्रस्तुतिकरण एवं परिचर्चा की गई। सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में डूबने की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से प्रभावित जिलों में समुदाय स्तर पर सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी हितधारकों से सहयोग प्रदान करने हेतु अपील की गई।

माननीय उपाध्यक्ष डॉ. उदय कांत द्वारा हरित क्षेत्र को बढ़ाने एवं बढ़ते तापमान का न्यूनीकरण करने के उद्देश्य से सुप्रसिद्ध एवं आजमाई हुई अकीरा मियावाकी तकनीक के द्वारा पुनर्वनीकरण करने हेतु सभी हितधारकों से आह्वान किया गया। उन्होंने प्रत्येक वर्ष गर्मी के बढ़ते प्रभाव पर गहरी चिंता व्यक्त की तथा अकीरा मियावाकी तकनीक से वृक्ष लगाकर जल, जीवन, हरियाली के फैलाव हेतु अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उक्त बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर विमर्श के उपरांत निम्नलिखित निर्णय किए गए :–

–सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024 के प्रथम फेज में राज्य में डूबने की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से प्रभावित जिलों में समुदाय स्तर पर सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम का संचालन अप्रैल से जून माह तक किया जाएगा।

–लू से बचाव हेतु प्राधिकरण की ओर से तैयार कार्ययोजना के आधार पर जिला प्रशासन व संबंधित विभाग लघुकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक गतिविधियों का क्रियान्वयन करेंगे। विभागों के द्वारा एवं जिलों के स्तर पर की जाने वाली पूर्व तैयारियों का सम्पादन ससमय किया जाएगा।

–सुरक्षित तैराकी के मास्टर ट्रेनर्स ने समय –समय पर बचाव गतिविधियों में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों को निर्धारित मानदेय दिए जाने का मामला उठाया। यह निर्णय किया गया कि विभिन्न जिलों के अपर समाहर्ता/आपदा प्रभारी इस संबंध में अनुरोध भेजेंगे, तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न अवसरों पर प्रशिक्षित वॉलेंटियर्स, जो विभिन्न कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित हुए हैं, को तैनात किया जाता है। इसके अतिरिक्त जन–जागरूकता एवं क्षमतावर्द्धन गतिविधियां की जानी है। विभिन्न अवसरों पर जिला के पदाधिकारियों के द्वारा इस प्रकार की तैनाती के दौरान भुगतान के प्रावधान का उल्लेख किया जाता है। इस बैठक में भी एक वॉलेंटियर्स ने अवगत कराया कि उन्होंने डूबने वाले व्यक्ति की लाश को निकालने

का कार्य किया, परन्तु उसका भुगतान नहीं किया गया। चूंकि इस प्रकार का विषय बार–बार उठाया जा रहा है। इसलिए इसका निराकरण आवश्यक है। उल्लिखित प्रत्युत्तर संबंधी कार्यों में वॉलेंटियर्स से सहयोग लेने की दशा में या उनके द्वारा कोई इस तरह का योगदान स्वयं दिया गया हो तो, उन्हे आबादी निष्क्रमण मद या अन्य उचित मद से जिला स्तर से भुगतान किया जाए।

–प्राधिकरण स्तर से समुदाय/ पंचायत/ प्रखण्ड/ जिला स्तर पर विभिन्न आपदाओं के प्रभाव को कम करने से सबंधित जागरुकता संबंधित हितभागियों के क्षमतावर्द्धन हेतु गतिविधि के अनुसार कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु 12 जिलों *(गया, नवादा, औरंगाबाद, बेगुसराय, मुजफ्फरपुर, जमुई, सीतामढी, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, बांका एवं खगडिया)* को 44,10,000/–की धनराशि उपलब्ध कराई गयी है। उक्त राशि का उपयोग वज्रपात से बचाव संबंधी जन जागरूकता गतिविधियों में किया जाना है। इन जिलों से राशि का उपयोग जन जागरूकता एवं क्षमतावर्द्धन गतिविधियों में करने हेतु पुनः अनुरोध किया गया।

-Emergency Essential Resource Reserve (EERR) किट के लिए नालंदा, पूर्वी चंपारण, अररिया, बांका, भागलपुर, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, गोपालगंज, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, पटना, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सिवान एवं वैशाली जिलों को निर्धारित राशि भेजी गई है। उक्त जिलों से इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मार्च माह, 2024 तक भेजने हेतु अनुरोध किया गया।

(B) वज्रपात से बचाव की कार्ययोजना के क्रियान्वयन पर बैठक आयोजित

वज्रपात से बचाव की कार्य–योजना के क्रियान्वयन के उद्देश्य से दिनांक 29 फरवरी, 2024 को विभिन्न हितधारकों के साथ एक बैठक प्राधिकरण के सभाकक्ष में आयोजित की गई। माननीय सदस्य श्री पी. एन.

राय की अध्यक्षता में तथा माननीय सदस्य श्री कौशल किशोर मिश्र की गरिमामयी उपस्थिति में उक्त बैठक संपन्न हुई। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग, कृषि विभाग, भवन विभाग, ऊर्जा विभाग, जीविका, बिहार मौसम सेवा केंद्र, भारतीय मौसम विभाग तथा वज्रपात संवेदनशील जिलों के अपर समाहर्ता एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री पी. एन. राय ने सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वज्रपात गंभीर प्राकृतिक आपदा के रूप में बिहार को हर साल प्रभावित करता है। राज्य में प्रत्येक वर्ष जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में दोपहर 12 से शाम 05 बजे के बीच वज्रपात की घटनाओं से सर्वाधिक लोग प्रभावित हुए है। इसलिए हमें सामूहिक प्रयास करते हुए वज्रपात से आम–जनमानस के बचाव हेतु कार्य योजना के अनुरूप विविध गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में प्राधिकरण द्वारा विकसित 'नीतीश' सुरक्षा कवच के माध्यम से वज्रपात के बारे में पूर्व सूचना प्रणाली सुदृढ़ होगी एवं बहुत ही कम समय में 'अलर्ट' लोगों को प्राप्त होंगे। उक्त बैठक में वज्रपात से बचाव से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विमर्श किया गया एवं निम्नलिखित निर्णय लिए गए :–

1. प्राधिकरण स्तर से *गया, औरंगाबाद, जमुई, बाँका, नवादा, पटना, नालंदा, भागलपुर, सारण, कैमुर, कटिहार, भोजपुर, पूर्णिया एवं पूर्वी चम्पारण जिलों* को वज्रपात से बचाव हेतु कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु प्राधिकरण स्तर से राषि उपलब्ध कराई गई है। इस राशि का उपयोग वज्रपात से बचाव हेतु विभिन्न गतिविधियों में किया जाना है। इस बैठक में जिलें के पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि राशि का उपयोग करके प्राधिकरण को शीघ्र सूचित किया जाए।
2. दक्षिणी बिहार के जिलों में वज्रपात प्रवण ग्रामीण अंचलों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए वर्ष भर वज्रपात सुरक्षा रथ, advisory, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर– बैनर तथा वीडियो फिल्मों के

माध्यम से सघन रूप से बचाव एवं जन–जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार किए जाने की महती आवश्यकता महसूस की गई।

3. बैठक में चर्चा के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि कृषि विभाग तथा पंचायती राज विभाग का पंचायत स्तर तक जन जागरूकता, प्रचार –प्रसार एवं संवाद का एक व्यवस्थित तंत्र है। इस माध्यम का उपयोग करके वज्रपात से बचाव एवं जनजागरूकता संबंधी फिल्मों को समुदाय तक पहुंचाए जाने का निर्णय लिया गया। उसी प्रकार आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी किए जाने वाले अलर्ट को इन विभागों को भेजा जाना चाहिए, जिससे जन समुदाय को ससमय सूचनाएं प्राप्त हो सकेंगी।
4. Indravajra App, सचेत App के माध्यम से जन समुदाय वज्रपात पूर्व चेतावनी के बारे में हितधारकों के माध्यम पहुंचाना सुनिश्चित किया जायेगा। जन–जागरूकता एवं क्षमतावर्द्धन के लिए जिलों को आपदा प्रबंधन विभाग से राशि उपलब्ध करने हेतु अनुरोध किया गया।
5. "नीतीश" पेंडेंट के माध्यम से वज्रपात से जन-समुदाय विशेषकर किसानों एवं अन्य पशुपालन कार्यों से जुड़े लोगों के बीच ससमय पूर्व सूचना पहुँचाई जाएगी। इस पेंडेंट को वज्रपात प्रवण प्रखंडों में प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। नीतीश पेंडेंट वाइब्रेशन, वॉयस मैसेज एवं लाइट इंडिकेटर के माध्यम से वज्रपात पूर्व चेतावनी देकर लोगों को सचेत कर उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा।
6. वज्रपात की स्थिति के संबंध में भारत मौसम विभाग, पटना के द्वारा एक लाभदायक प्रस्तुति की गयी। यह प्रस्तुति निरोधात्मक एवं शमात्मक कार्य के लिये उपयोगी हो सकती है।

प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष ठनका आपदा का अध्ययन करता है जिसके लिए घटनाओं से संबंधित आंकड़ों की आवश्यकता होती है। आंकड़ा संकलित करने के लिए एक विहित प्रपत्र बनाया गया है। उसे पुनः सभी जिलों, जो मुख्य रूप से प्रभावित है, को भेजा जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग को भी यह प्रपत्र भेज जाएगा। वर्ष–2024 की घटनाओं का प्रतिवेदन इसी प्रपत्र के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(C) सामुदायिक स्वयंसेवकों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण का प्रशिक्षण

हमारा बिहार बहु–आपदा प्रवण राज्य है। फलत : हमारे गांव, पंचायतों, प्रखंड एवं जिलों में विभिन्न तरह की आपदाएं आती रहती हैं। पंचायतों में कुछ नौजवान आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन हेतु जरूरी ज्ञान और हुनर सीख लें, तो वे अपने जिले को आपदाओं से सुरक्षित रख सकते हैं। इस उद्देश्य हेतु प्रशिक्षण के माध्यम से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य के नौजवानों/नवयुवतियों को प्रशिक्षित कर आपदाओ के प्रत्युत्तर हेतु तैयार कर रहा है। इसी क्रम में फरवरी–2024 माह में दिनांक 31–01–2024 से 11–02–2024 तक सिविल डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बिहटा, पटना में 12 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया। इसमें गोपालगंज एवं मधुबनी जिले के कुल 60 युवाओं ने भाग लिया। इसी माह सामुदायिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण का दूसरा बैच भी यहीं दिनांक 14–02–2024 से 25–02–2024 तक आयोजित किया गया। इस बैच में मधेपुरा और सीवान जिले के कुल 72 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया। प्राधिकरण की ओर से राज्य भर में अब तक कुल 18 बैच में लगभग 11 हजार स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(D) बालासोर दुर्घटना :पीड़ितों के पुनर्वास व पुनर्प्राप्ति का समन्वित प्रयास

विगत दो जून, 2023 को बालासोर ट्रेन हादसे के बाद बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व में समाज कल्याण विभाग, जीविका (ग्रामीण विकास विभाग), बीआईएजी, रिलायंस फाउंडेशन, यूनिसेफ और अन्य इच्छुक हितधारकों की साझेदारी के साथ पीड़ितों एवं परिवारों के सहयोग हेतु समन्वित पहल शुरू की गई। यह आज भी जारी है। पीड़ितों एवं परिवार के जरुरतमंदों को सहायता, पुनर्वास, रेल दावा ट्रिब्यूनल में दावा आवेदन एवं अन्य तकनीकी सहयोग, रिलायंस के समन्वय उनके पुनर्वास हेतु तथा विभागों के सहयोग से सरकार की विभिन योजनाओं का लाभ, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक सलाह इत्यादि कार्य आज भी जारी है। माननीय उपाध्यक्ष की सोच एवं उनकी भावनाओं के अनुरूप प्राधिकरण ने इस प्रयास को अंतिम मुकाम तक पहुँचाने का फैसला लिया है जिसके तहत हर पीड़ित जरूरतमंद तक पहुँचना है।

प्राधिकरण के सतत प्रयास एवं सहयोग से रिलायंस फाउंडेशन ने पशुधन सहयोग के लिए चिन्हित परिवारों के साथ पशुधन एजेंसी द्वारा संपर्क किया गया एवं उनके लिए पशुधन के प्रकार को तय किया गया। बिहार से 38 पीड़ित परिवारों की सूची उन्होंने साझा की है, जिनको पशुधन सहयोग दिया जाना है। इस कार्य को मूर्तरूप देने के लिए वेंडर का भी चयन उन्होंने कर लिया है एवं उनकी विभागीय प्रकिया पूरी हो गयी है। नौकरी एवं कौशल प्रशिक्षण हेतु चिन्हित पीड़ित परिवारों के बीच दीर्घकालीन योजना पर वे कार्य कर रहे हैं। आतंरिक विभागीय प्रक्रिया में समय लग रहा है। इस संबंध में जल्द सूचित करने का उन्होंने आश्वासन दिया है।

पीड़ित परिवारों से कुछ बच्चों को शिक्षा हेतु दीर्घकालीन सहयोग की आवश्यकता महसूस हुई। तत्काल अडाणी फाउंडेशन से संपर्क किया गया एवं उन्हें इस कार्य में सहयोग का आग्रह किया गया , लेकिन अभी तक अडाणी फाउंडेशन से जबाब नहीं आया है।

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस), मुंबई की द्वितीय वर्ष की छात्रा सुश्री सपना कुमारी ने अनुमोदनोपरान्त प्राधिकरण में 03 महीने के इंटर्नशिप के लिए 27 फरवरी, 2024 को योगदान दिया है। इस इंटर्नशिप का उद्देश्य है :

- प्राधिकरण से जुड़कर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी समझ को व्यापक बनाना और उनके कौशल को तेज करना।
- बालासोर ट्रेन हादसे के संवेदनशील–कमजोर जीवित बचे लोगों के लिए सूक्ष्म पुनर्प्राप्ति योजना बनाना और उसका क्रियान्वयन करना।
- अपकेन्द्रीय आपदाओं (सेन्ट्रीफ्यूगल डिजास्टर) और उस पर सरकार के स्तर से प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए राज्य के लिए ड्राफ्ट नीति तैयार करना
- प्राधिकरण के किन्हीं दो प्रमुख कार्यक्रमों का संकलन और समीक्षा करना और उसके मूल्यांकन के लिए कार्यप्रणाली तैयार करना।

(E) डीआरआर रोडमैप अद्यतीकरण

यूनिसेफ द्वारा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (डीआरआर) रोडमैप के अद्यतीकरण (संशोधन) का कार्य अंतिम चरण में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय की सोच के अनुरूप नए संदर्भों में एवं व्यावहारिकता को ध्यान में रख ड्राफ्ट का पुनर्लेखन किया गया, सभी सुझावों एवं संशोधनों को इसमें सन्निहित कर लिया गया है। निदेशानुसार यूनिसेफ द्वारा रोडमैप के हिंदी अनुवाद का भी कार्य शुरू हो रहा है।

विभागवार पुस्तिका पर भी कार्य चल रहा है। शिक्षा विभाग की पुस्तिका के आरंभिक प्रारूप में संशोधन हेतु सुझाव दिया गया है। इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद अन्य विभागों की पुस्तिका तैयार की जाएगी। तत्पश्चात संबंधित विभागों के साथ उन्मुखीकरण कार्यशाला की जानी है। इसे यूनिसेफ की सुश्री वंदना की उपलब्धता के अनुसार एवं प्राधिकरण की सुविधा को ध्यान में रख जल्द ही संपन्न किया जा सकता है।

हीट एक्शन प्लान अद्यतीकरण एवं कोल्ड एक्शन प्लान :

हीट एक्शन प्लान अद्यतीकरण एवं कोल्ड एक्शन प्लान बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ (आईआईपीएच), गांधीनगर के साथ संपन्न सहमति पत्र (एमओयू) के तहत कार्य चल रहा है।

आईआईपीएच, गांधीनगर ने 31 जनवरी, 2024 तक कोल्ड एक्शन प्लान का पहला ड्राफ्ट प्रस्तुत किया। संस्थान द्वारा दिए गए ड्राफ्ट पर असंतोष जाहिर किया गया क्योंकि यह स्वीकार्य स्तर का नहीं था। संस्थान के साथ माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्यों एवं सभी प्रोफेशनल्स के साथ 04 एवं 05 फरवरी को चर्चा के आलोक में पुनः संशोधित ड्राफ्ट दिया गया। लेकिन यह ड्राफ्ट भी स्वीकार्य स्तर का नहीं था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्य श्री पी. एन. राय ने अपने विचार दिए। डीआरआर रोडमैप एवं एनडीएमए के कोल्ड एक्शन प्लान मार्गदर्शिका के आलोक में ड्राफ्ट को पुनः तैयार करने को कहा गया, जो प्राप्त हो चुका है। इसका अध्ययन किया जा रहा है।

हीट एक्शन प्लान का भी ड्राफ्ट (जो 31 जनवरी, 2024 तक दिया जाना था) 27 फरवरी को प्राप्त हो गया। आरंभिक स्तर ही ड्राफ्ट में अनेक विसंगतियां पाई गयीं। संस्थान के साथ ऑनलाइन बैठक की गयी एवं उनको पुनर्लेखन के लिए कहा गया है। स्वीकार्य ड्राफ्ट प्राप्त होने पर माननीय उपाध्यक्ष के अवलोकन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

जलवायु परिवर्तन शमन एवं अनुकूलन सम्बंधित कार्य :

15 फरवरी, 2024 को ऑनलाइन मोड में माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में विश्व स्वास्थ्य संगठन (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन–डब्ल्यूएचओ) के साथ आयोजित बैठक में बिहार स्वास्थ्य समिति के वरिष्ठ अधिकारियों और आईएमए, पटना के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य डब्ल्यूएचओ के सहयोग से बिहार में जलवायु विशेषतः गर्मी से संबंधित बीमारियों के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा क्षमतावर्द्धन करना है। बैठक में यह निर्णय किया गया कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से एक व्यापक कार्य योजना तैयार करेगा। इस योजना को बिहार स्वास्थ्य समिति के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य की क्षमता को बढ़ाना है ताकि जलवायु परिवर्तन से विशेषतः गर्मी से होने वाली बीमारियों का सामना किया जा सके एवं प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके। डब्ल्यूएचओ, नई दिल्ली के साथ परामर्श कर क्षमता निर्माण और जलवायु परिवर्तन से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए कार्य योजना का विवरण तैयार किया गया है। उपरोक्त कार्य योजना को निरंतर आधार पर लागू करने में डब्ल्यूएचओ, नई दिल्ली का तकनीकी सहयोग सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध पत्र दिया जाना आवश्यक है।

यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी अप्रैल से जून के दौरान अपेक्षित गर्मी को ध्यान में रखते हुए और आपदा (आपातकालीन) पूर्व तैयारियों एवं प्रतिक्रिया में सुधार करने के लिए, बिहार स्वास्थ्य समिति डब्ल्यूएचओ के तकनीकी सहयोग से 'गर्मी से संबंधित बीमारी – प्रबंधन और रिपोर्टिंग' पर क्षमता निर्माण कार्यशाला की योजना बना सकता है और इसके लिए उपयुक्त प्रस्ताव प्राधिकरण को विचार के लिए भेज सकता है। तदनुसार, बिहार स्वास्थ्य समिति से इसी प्रकार का अनुरोध किया गया है। इस प्रस्ताव पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति मिल चुकी है। तदनुसार कार्य प्रगति पर है।
जलवायु परिवर्तन शमन एवं अनुकूलन के क्षेत्र में क्षमता विकास एवं संवेदीकरण–जागरूकता के लिए सम्बंधित विषयों पर स्वास्थ्य विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, कृषि विभाग, नगर विकास विभाग एवं जल संसाधन विभाग के साथ संयुक्त कार्यक्रमों की रूपरेखा पर कार्य करने की योजना है। संबंधित विभाग से मिलकर कार्य योजना बनाई जानी है।

आपदा प्रबंधन में एआर, वीआर मॉडल एवं एआई की भूमिका :

आपदा प्रबंधन में एआर, वीआर एवं 3डी मॉडल पर एक कांसेप्ट नोट तैयार किया गया जिसे आगे बढाने पर सहमति बनी। आपदा प्रबंधन में तैयारी, प्रतिक्रिया, शमन, जागरूकता एवं क्षमता निर्माण इन मॉडल्स के माध्यम से प्राधिकरण का क्षमतावर्द्धन किया जा सकता है। इस कार्य हेतु एक कंसल्टेंट नियोजित करने का निर्णय हुआ है। PwC, KPMG, Deloit से ईमेल द्वारा पत्राचार किया गया है। जवाब की प्रतीक्षा अभी तक होती रही है। निदेशानुसार अन्य सॉफ्टवयेर संस्थाओं से भी संपर्क किया गया। मुंबई की कंपनी टेक्नोट्रोव से संपर्क किया गया। भूकम्प एवं अग्निशमन पर उनका प्रस्तुतीकरण प्रोफेशनल स्तर पर किया गया। 04 सॉफ्टवेयर संस्थानों द्वारा उनके वीआर मॉडल (आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में) एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधनों में भूमिका पर प्रस्तुतीकरण किया गया है। TCS के साथ भी संपर्क किया गया है। उनसे प्रस्ताव अपेक्षित है।

(F) स्वास्थ्य कर्मियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

किसी भी आपदा में अस्पताल प्रभावित होने वाला पहला संस्थान होता है क्योंकि घटना के बाद प्रभावित समुदाय अस्पतालों का ही रूख करता है। आपदा के दौरान पीड़ित समुदाय को प्रभावी व त्वरित चिकित्सा सेवा मुहैया कराने के लिए जरूरी है कि आपातकालीन स्वास्थ्य प्रणाली योजना तैयार की जाय। इस संबंध में स्वास्थ्यकर्मियों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में संवेदनशील बनाना आवश्यक है ताकि प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं से स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान कर उसका समुचित एवं त्वरित प्रबंधन किया जा सके। इसी क्रम में प्राधिकरण एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के संयुक्त तत्वावधान में फरवरी माह में दिनांक 12–13 फरवरी एवं 19–20 फरवरी 2024 के अन्तराल में दो बैचों में राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के फीडबैक सत्र में प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष डा. उदय कांत ने प्रतिभागियों के बीच अस्पताल आकस्मिक प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। खासकर अग्निकांड से किस तरह से अस्पताल को सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने बिहार स्टेट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क (BSDRN) मोबाईल एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी कि किसी भी आपातकालीन में यह एप्लीकेशन कैसे त्वरित मदद पहुंचा सकता है। विभिन्न प्रकार की आपदाओं की पूर्व चेतावनी हेतु आईआईटी, पटना के सहयोग से तैयार किए गए सुरक्षा कवच 'नीतीश पेंडेंट' के बारे में भी जानकारी दी गई। आयोजित प्रशिक्षण में भोजपुर, रोहतास, बक्सर, नालन्दा, पटना, कैमूर, अरवल, औरंगाबाद, गया, सीवान, सारण, नवादा, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा एवं गोपालगंज जिले से आकस्मिकी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, जिला अस्पताल के प्रबंधक, जिला अस्पताल के सीनियर नर्सिंग स्टाफ एवं बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक ने भाग लिया।

(G) आपदाओं से बचाव हेतु जिलों में तैयार हो रही मॉकड्रिल टीम

जिला स्तर पर मॉकड्रिल कोर टीम के नौ दिवसीय प्रशिक्षण के लिए प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) एवं अग्निशाम सेवा के सहयोग से प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है। इसके आधार पर नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, बिहटा जिला कोर टीम का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा है। पटना जिले में जून 2024 तक अनुमोदित कार्यक्रम कैलेन्डर के अनुरूप मॉकड्रिल कार्यक्रम दिसम्बर माह से शुरू हो गया है। जनवरी तथा फरवरी माह में भी कैलेन्डर के अनुसार मॉकड्रिल कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुछ विद्यालयों में परीक्षाओं को ध्यान में रख मॉकड्रिल की तिथि में आवश्यक संशोधन किया गया।

2. अनुभवी राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भूकंप के दौरान आवासीय भवनों समेत अन्य संरचनाओं को होनेवाले नुकसान को कम करने के उद्देश्य से राज्य भर में असैनिक अभियंताओं व अनुभवी राजमिस्त्रियों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में लगभग 5000 अभियंताओं, वास्तुविदों एवं संवेदकों तथा करीब 20,000 अनुभवी राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आपदा प्रबंधन के बदले परिदृश्य में भूकंपरोधी भवनों के निर्माण को बढ़ावा देने एवं पूर्व में निर्मित मकानों की रेट्रोफिटिंग कर उन्हें भूकंपरोधी बनाने की दिशा में प्राधिकरण कार्य कर रहा है। अनुभवी राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को बेहतर और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार की संस्था नेशनल स्किल डेवलेपमेंट कौंसिल (एनएसडीसी) के साथ प्रस्तावित एमओयू के सन्दर्भ में संशोधित ड्राफ्ट दुबारा प्राधिकरण को प्राप्त हुआ जिस पर फिर से विधिक परामर्श लिया गया। माननीय उपाध्यक्ष के निदेशानुसार इसे अन्तिम रूप देने हेतु एनएसडीसी से समन्वय का कार्य किया गया । अनुबंध का संशोधित प्रारूप एनएसडीसी से दो फरवरी को प्राप्त हुआ है जिसपर प्राधिकरण भी सहमति है। तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

3. बी एस टी एन (बिहार सिस्मिक टेलीमेट्री नेटवर्क) की स्थापना

बिहार सिस्मिक टेलीमेट्री नेटवर्क (बीएसटीएन) की स्थापना से संबंधित उपकरणों की प्राप्ति हेतु बिहार मौसम सेवा केंद्र द्वारा तैयार किए गए आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) को पुनरीक्षण व संपुष्टि (वेट्टिंग) हेतु विशेषज्ञों को भेजा गया था। उनसे प्राप्त सुझाव के शामिल करते हुए संशोधित आरएफपी बिहार मौसम सेवा केंद्र से प्राप्त हुआ जिसे अग्रेतर कार्यवाही हेतु सचिव को पृष्ठांकित किया गया। बीएसटीएन के भवन निर्माण में हुई त्रुटि एवं जल रिसाव को ठीक करने के बिंदु पर आवश्यक निदेश भवन निर्माण निगम को दिया गया है। इन भवनों का निरीक्षण बिहार मौसम सेवा केंद्र के संयुक्त निदेशक डॉ० सी.एन. प्रभु द्वारा निगम के अभियंताओं के साथ संयुक्त रूप से मार्च माह, 2024 में किया जाना है।

(H) बीएसडीआरएन ऐप के व्यापक इस्तेमाल हेतु जिलों में बैठक

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनवरी माह में लांच की गई बिहार में बिहार स्टेट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क (बीएसडीआरएन) मोबाइल ऐप के माध्यम से आपदाओं के दौरान त्वरित कार्यवाई गोल्डन ऑवर के अंदर संभव है। बीएसडीआरएन वेब पोर्टल पर अभी तक उपलब्ध लगभग 65,000 आंकड़ों के समुचित इस्तेमाल हेतु एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके निम्नांकित उपयोग हैं –

1. बीएसडीआरएन पर उपलब्ध आंकड़ों का चलंत अवस्था में भी त्वरित आहरण
2. दूरभाष संपर्क द्वारा सीधे संसाधनों की प्राप्ति
3. व्हाट्सअप द्वारा सूचना का सुगम आदान– प्रदान
4. सोशल मीडिया पर सूचनाओं का सुगम आदान–प्रदान जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि
5. टेक्स्ट मैसेज का आदान–प्रदान
6. संसाधनों की गूगल मैप पर अवस्थिति
7. सभी संसाधनों की जियो टैगिंग
8. उपलब्ध संसाधनों की त्वरित खोज 5/10 किलोमीटर के दायरे से लेकर 90 किमी तक में

इसके एप के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु एवं आपदाओं के दौरान विभिन्न जिलों में इस्तेमाल करने हेतु विस्तृत योजना राज्यभर के लिए तैयार की गई है। पायलट के तौर पर गया जिला का चयन किया गया है तथा प्राधिकरण की टीम अन्य जिलों में जाकर बैठक कर इसकी उपयोगिता के बारे में सरकारी महकमे से जुड़े लोगों को जागरूक करेगी ताकि गोल्डन ऑवर में बिना समय नष्ट किए त्वरित कार्रवाई कर लोगों की जान आपदाओं से बचाई जा सके। एप के विशिष्ट फीचर्स के बारे में जिलों में बैठक कर जानकारी देते हुए आपदाओं के दौरान इसके व्यापक इस्तेमाल पर बल दिया जायेगा।

2. जिलास्तरीय आपदा प्रबंधन पदाधिकारियों हेतु एक दिवसीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण उन्नमुखीकरण कार्यक्रम के संबंध में शेष बच गए जिलों के लिए दूसरी ट्रेनिंग का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (डीएमआई), पटना के साथ संयुक्त रूप से करने हेतु प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग को डीएमआइ को निदेशित करने हेतु पत्र भेजा गया है। विभागीय पत्रांक 339 दिनांक 5–2–24 पर डीएमआइ द्वारा अग्रेतर कार्यवाही अपेक्षित है।

3. स्थानीय शहरी निकायों के कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर प्रशिक्षण देने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है।

(I) शहरों में जल जमाव की समस्या से निपटने पर विमर्श

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में दिनांक 18 फरवरी को प्राधिकरण सभाकक्ष में पटना समेत राज्य के अन्य शहरों में जल जमाव की समस्या से निपटने पर एक उच्चस्तरीय बैठक में विचार–विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष डॉ उदयकांत ने की। इस मौके पर माननीय सदस्य श्री पी. एन. राय की गरिमामयी उपस्थिति रही। बैठक में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना एवं बिहार मौसम सेवा केंद्र, पटना के वरिष्ठ वैज्ञानिक, प्राध्यापक व प्रोफेशनल्स के साथ– साथ पटना नगर निगम व पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वरीय पदाधिकारी व अभियंता भी मौजूद थे।

मानसून के आगमन से पूर्व जल–जमाव की समस्या से निपटने के लिए पटना नगर निगम को क्या–क्या पूर्व तैयारी करनी चाहिए, इस पर विचार किया गया। इस समस्या से निजात के लिए आईआईटी के विशेषज्ञ ने दीर्घकालिक उपायों की चर्चा की। पूरे पटना शहरी क्षेत्र में सेंसर लगाने पर सहमति जताई गई। बैठक में आईआईटी, पटना के निदेशक प्रोफेसर टी. एन. सिंह, आईआईटी, दिल्ली के प्रोफेसर डॉ. के. एन. झा, आईआईटी, पटना के प्रोफेसर डॉ. ए.के. वर्मा, आईआईटी, दिल्ली के प्रोफेसर ए.के. गोसाईं, बिहार मौसम सेवा केंद्र के संयुक्त निदेशक डॉ. सी.एन. प्रभु, पटना नगर निगम के चीफ इंजीनियर सुरेंद्र कुमार सिन्हा आदि मौजूद थे।

(J) O2B2 संस्था प्राधिकरण के साथ मिलकर करेगी काम

विदेशों में रह रहे प्रवासी बिहारियों को अपने मूल जन्मस्थान बिहार की चिंता है। राज्य के विकास के लिए वे हर सहयोग को तैयार हैं। बिहार के मूल निवासियों की ऐसी ही एक संस्था ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेटर बिहार (O2B2) अमेरिका सहित कई देशों में कार्यरत है। आपदाओं से लड़ने में यह संस्था बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर काम करेगी। O2B2 संस्था से जुड़ीं मनीषा पाठक दिनांक 8 फरवरी को प्राधिकरण सभागार में प्रोफेशनल्स के साथ संवाद कर रही थीं। इस अवसर पर प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष डॉ उदय कांत, माननीय सदस्य श्री पी. एन. राय और माननीय सदस्य श्री कौशल किशोर मिश्र की गरिमामयी उपस्थिति रही। बैठक में मौजूद आईआईटी, पटना के प्रोफेसर डॉ राजीव मिश्र ने संस्था को 'नीतीश' पेंडेंट के बारे में अवगत कराया, जो आपदाओं की पूर्व सूचना देने में कारगर है। संस्था ने इस पेंडेंट के निर्माण में सहयोग का वचन दिया ताकि इसे आम लोगों को सुलभ कराया जा सके।

(K) प्रख्यात कैंसर रोग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने 'इनसे मिलिए' कार्यक्रम में स्वस्थ रहने के बताए गुर

पटना के जाने–माने कैंसर रोग विशेषज्ञ पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह 27 फरवरी को सरदार पटेल भवन स्थित प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे। 'इनसे मिलिए' कार्यक्रम में प्राधिकरण के पदाधिकारियों, कर्मियों और प्रोफेशनल्स को संबोधित किया। इस अवसर पर प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष डॉ उदय कांत, माननीय सदस्य श्री पी. एन. राय, माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार वर्मा, माननीय सदस्य श्री कौशल किशोर मिश्र की गरिमामयी उपस्थिति रही। प्राधिकरण के सचिव श्री मीनेंद्र कुमार (भा.प्र.से.) ने प्लांट बुके देकर डॉ. सिंह का स्वागत किया।

अपने संबोधन में डॉ. सिंह ने प्राधिकरण कर्मियों को स्वस्थ रहने के गुर बताए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश में हेल्थ सेक्टर सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने होगा। आज की तारीख में 10 में से एक व्यक्ति कैंसर का रोगी है। हर 40 सेकंड पर कैंसर की वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। देश में प्रतिवर्ष 38 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि कैंसर के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि इस रोग के लक्षण या इससे होनेवाली तकलीफें बिल्कुल एडवांस स्थिति में ही सामने आती हैं। तब तक काफी देर हो चुकी होती है। कैंसर के इलाज में समय का महत्व सबसे ज्यादा

है। 88 प्रतिशत रोगी कैंसर की अंतिम अवस्था (एडवांस स्टेज) में ही डॉक्टर के पास पहुंच पाते हैं। यह सबसे दुखद स्थिति है और इस रोग से मृत्यु दर अधिक होने की सबसे बड़ी वजह भी यही है।

डॉ. सिंह ने कहा कि हमारे देश में स्तन कैंसर के मामले सबसे ज्यादा आते हैं। महिलाओं में जागरूकता की कमी इसका सबसे प्रमुख कारण है। इसके बाद मुंह का कैंसर है, जिसकी सबसे बड़ी वजह तंबाकू का सेवन है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा कैंसर बांट रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश में 300 करोड रुपए का व्यापार गुटखे का होता है।

भविष्य की अपनी योजनाओं का जिक्र करते हुए डॉ. सिंह ने बताया कि हाजीपुर में हुए एक बड़ा कैंसर अस्पताल बनना चाह रहे हैं। यह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। यहां लोगों को उचित दर पर कैंसर के इलाज की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि कैंसर की रोकथाम के लिए जागरूकता सबसे जरूरी है। हेल्थ एजुकेशन, मेडिटेशन, योगासन, साफ पानी का सेवन, हेल्दी फूड, स्वच्छ पर्यावरण, सफाई ये सब चीजें जरूरी है। इन सब की बदौलत ही कैंसर के मामले कम किए जा सकते हैं। कैंसर रोग के बारे में बच्चों को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए।

डॉ. सिंह ने कहा कि कैंसर की रोकथाम के लिए सबसे ज्यादा कारगर गांव में मौजूद चिकित्सक हो सकते हैं, जिन्हें हम झोलाछाप डॉक्टर के रूप में जानते हैं। उनका ग्रामीणों से सीधा संवाद होता है। संदेश होता है। कैंसर या किसी भी अन्य बीमारी की रोकथाम के लिए ये सबसे कारगर हो सकते हैं। उन्हें बस कायदे से प्रशिक्षित और जागरूक करने की जरूरत है। नई तकनीक की चर्चा करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कैंसर के इलाज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) भी मददगार हो सकता है। इस दिशा में हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में तेजी से काम हो रहा है। इस जानलेवा रोग से बचने के उपायों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि हर आदमी को साल में एक बार अपने पूरे शरीर का हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। साथ ही कुछ सामान्य लक्षण हैं, जिन पर खास ध्यान देना चाहिए। मसलन, शरीर में कोई भी गांठ लंबे समय से ठीक नहीं हो रही हो। मुंह, पेशाब या मल के रास्ते से खून आए तो यह बात गंभीर है। लगातार खांसी हो रही हो। मुंह के अंदर सफेद रंग के धब्बे नजर आते हों। शरीर पर तिल या मस्सा अपना रंग और आकार बदल रहा हो तो तुरंत सचेत हो जाएं। ये सारे लक्षण अगर दिखें तो फौरन किसी अच्छे चिकित्सक से दिखाएं। अपना इलाज कराएं।

एसएस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, कंकड़बाग, पटना के निदेशक डॉ. जितेंद्र कुमार सिंह कैंसर रोग की चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में विख्यात नाम हैं। डॉ जितेंद्र कुमार सिंह का जन्म बांका जिले के मंझौनी गांव में एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में हुआ। वर्ष 1975 में पटना मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। पीएमसीएच में वर्षों सेवा देने के उपरांत महावीर कैंसर संस्थान के निदेशक रहे। वर्ष 2012 में चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से नवाज गया।

(L) साइन लैंग्वेज वर्कशॉप का आयोजन

दिव्यांगजन आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसका मकसद दिव्यांगजनों को आपदाओं में सुरक्षित रखना है। दिव्यांगजनों की दिक्कतों को भलीभांति समझने एवं उनके प्रति और ज्यादा संवेदनशील आचरण व व्यवहार अपनाने के उद्देश्य से प्राधिकरणकर्मियों के बीच साइन लैंग्वेज (मूक–बधिर की भाषा) वर्कशॉप का आयोजन किया गया। सप्ताहव्यापी इस वर्कशॉप में प्राधिकरणकर्मियों को इंडियन साइन लैंग्वेज की बेसिक जानकारी दी गई। डेफ वूमेन फाउंडेशन ऑफ बिहार के सहयोग से यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 फरवरी से 16 फरवरी के बीच आयोजित किया गया। साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट के रूप में श्री जितेंद्र कुमार और सुश्री मोनिका सिंह मौजूद रहे। वर्कशॉप में प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष डॉ उदय कांत, माननीय सदस्य श्री पी. एन. राय और माननीय सदस्य श्री कौशल किशोर मिश्र की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। समस्त प्रतिभागियों को फाउंडेशन की ओर से सर्टिफिकेट प्रदान किए गए।

(M) फरवरी माह में मीडिया में प्राधिकरण की गतिविधियों की कवरेज

वज्रपात, बाढ़, लू और शीतलहरी जैसी अनेक आपदाओं की पूर्व चेतावनी देगा 'नीतीश' पेंडेंट

- वज्रपात से होनेवाली मौत में आएगी कमी
- सेटेलाइट और मौसम विज्ञान केंद्र से जुड़ा होगा पेंडेंट

पटना, संवाददाता

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय में राज्य को जीवन सुरक्षा लॉकिट तथा बीएसडीआरएन के रूप में आपदा प्रबंधन के लिए दो सौगात दी। राज्य में वज्रपात एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं को उन्होंने बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, डा. उदयकांत को इससे निपटने के उपाय ढूंढने का निर्देश दिया था। वैसे तो अब तक आपदा प्रबंधन विभाग की ओर वज्रपात की पूर्व चेतावनी देने के लिए, इंद्रवज्र नामक एप बनवाया गया जो मोबाइल पर वज्रपात के आसन्न खतरे की पूर्व सूचना दे सकता है। इसके साथ ही अति संवेदनशील चिह्नित गांवों में जल मीनारों व ऊंची इमारतों पर तेज ध्वनि विस्तारक यंत्र (हूटर) लगाकर लोगों को पूर्व चेतावनी देने का काम भी किया जा रहा था लेकिन इन तमाम प्रयत्नों के बावजूद वज्रपात से होने वाली मौतों की संख्या में कोई खास कमी नहीं आई। इसकी वजह यह थी कि दूर खेतों में काम कर रहे कृषि कर्मियों के पास न तो मोबाइल होता था न और ही हूटर की आवाज पहुंचती थी। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आईआईटी, पटना के तकनीकी सहयोग से एक ऐसा पेंडेंट बनाया है जो प्राकृतिक आपदा की पूर्व जानकारी देगा। इस डिवाइस का नाम 'नीतीश' रखा गया है। यह डिवाइस मानव शरीर की गर्मी से चार्ज होगा। इसे शरीर में बांध कर रखना होगा।

आईआईटी, पटना के निदेशक, डॉ. त्रिलोकीनाथ सिंह के दिशा-निर्देश में कम्प्यूटर साइंस

विभागाध्यक्ष प्रो. राजीव मिश्रा, डॉ. अरजीत रॉय एवं आकाश ने गहन अन्वेषण के उपरांत एक नीत, तीव्र, एवं शक्तिशाली (नीतीश) का निर्माण किया।

यह सामान्य कलाई घड़ी के जैसा ही 47 मिमी x 48 मिमी x 16 मिमी एवं मात्र 43 ग्राम वाले इस पेंटेड है। इसे आसानी से गले में लटकाया या बांह पर बांधा जा सकता है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ उदय कान्त बताते हैं कि 'नीतीश पेंडेंट' की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शरीर की ऊर्जा और गर्माहट से ही रिचार्ज होता रहता है। क्षेत्र विशेष में वज्रपात या किसी अन्य आपदा की पूर्व चेतावनी पेंडेंट के स्वामी को तीन प्रकार से मिलेगी। पहले उसे वॉयस मैसेज सुनाई देगा। वह वाईब्रेट भी करेगा तथा इसका रंग हरे से लाल हो जायेगा

जब तक इसे पहनने वाला स्विच ऑफ न कर दे तब तक नीतीश पेंडेंट चेतावनी देता ही रहेगा। स्विच ऑफ करते ही प्राधिकरण के कम्प्यूटर में यह सूचना स्वतः ही आ जाएगी कि व्यक्ति विशेष तक चेतावनी पहुँच चुकी है। नीतीश पेंडेंट वाटरप्रूफ भी है जिसे समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 100 फीसद सुरक्षित है। बिहार मौसम सेवा केन्द्र के सहयोग से यह वज्रपात के साथ साथ बाढ़, लू और शीतलहरी की पूर्व चेतावनी देगा।

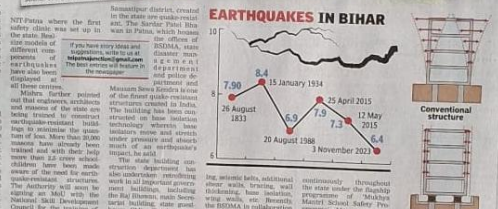

आईआईटी, पटना एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच हुए एमओयू के तहत आईआईटी इसके 1 लाख पीस का निर्माण करेगा। आईआईटी के प्रोफेसर डा. राजीव मिश्रा ने बताया है कि शीघ्र ही नीतीश पेंडेंट का पेटेंट प्राधिकरण एवं आईआईटी के संयुक्त नाम से कराया जाएगा। अभी इसके पुर्जों में एक को आयातित करना पड़ रहा है इस कारण नीतीश पेंडेंट की लागत करीब 1000 रुपए के करीब होगी। प्रयास यह है कि आयातित पुर्जे को यहीं बना लिया जाए। ऐसा होने से इसकी कीमत में 20 प्रतिशत कमी आने की संभावना है।

(N) अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम

'अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम' के तहत '16 बिंदु अग्नि प्रवणता सूचकांक' के आधार पर फरवरी माह में राज्य के कुल 358 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया जिसमें 20 सरकारी एवं 338 निजी अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों का निरीक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देश में अग्निशाम सेवाएं के अधिकारियों द्वारा किया गया, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

Month Feb -2024, Update Status of Covid & Non-Covid Hospitals Fire Audit report Districtwise

Sr. No	District	Covid Hospital			Non-Covid Hospital		
		Governmental	Private	Total	Governmental	Private	Total
1	Patna	0	0	0	1	38	39
2	Nalanda	0	0	0	0	10	10
3	Rohtas	0	0	0	1	4	5
4	Bhabhua	1	0	1	0	6	7
5	Bhojpur	0	0	0	0	2	2
6	Buxar	0	0	0	0	5	5
7	Gaya	0	0	0	0	11	11
8	Jehanabad	0	0	0	0	5	5
9	Arwal	0	0	0	0	5	5
10	Nawada	0	0	0	0	7	7
11	Aurangabad	0	0	0	1	3	3
12	Chhapra	0	0	0	0	5	5
13	Siwan	0	0	0	0	17	17
14	Gopalganj	0	0	0	0	4	4
15	Muzaffarpur	0	0	0	0	21	21
16	Sitamarhi	0	0	0	0	20	20
17	Sheohar	0	0	0	0	0	0
18	Bettiah	0	0	0	0	2	2
19	Bagaha	0	0	0	0	0	0
20	Motihari	0	0	0	5	15	20
21	Vaishali	0	0	0	0	12	12
22	Darbhanga	0	0	0	2	11	13
23	Madhubani	0	0	0	0	2	2
24	Samastipur	0	0	0	0	8	8
25	Saharasa	0	0	0	0	11	11
26	Supaul	0	0	0	0	5	5
27	Madhepura	0	0	0	0	2	2
28	Purnea	2	2	4	0	12	12
29	Araria	0	0	0	1	3	4
30	Kishanganj	0	0	0	0	12	12
31	Katihar	0	0	0	1	15	16
32	Bhagalpur	0	0	0	0	19	19
33	Naugachhia	0	0	0	0	0	0
34	Banka	0	0	0	0	3	3
35	Munger	0	0	0	0	2	2
36	Lakhisarai	0	0	0	3	1	4
37	Shekhpura	0	0	0	0	3	3
38	Jamui	0	0	0	0	9	9
39	Khagaria	0	0	0	1	8	9
40	Begusarai	0	0	0	1	18	19
Total		3	2	5	17	336	353

इस प्रकार राज्य के अब तक कुल 12,509 अस्पतालों का अग्नि प्रवणता सूचकांक के आधार पर निरीक्षण किया जा चुका है।

(O) फरवरी माह की व्यय विवरणी (रुपये में)

व्यय विवरणी (फरवरी - 2024)		
A	**31-04 (वेतन)**	24,96,911
B	**31-06** (गैर-वेतन)	
1	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं	9,64,074
2	कार्यालय व्यय	3,20,158
3	जन जागरुकता	33,630
4	सुरक्षित तैराकी	20,000
5	मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम	3,03,681
6	जीविका दीदी प्रशिक्षण	4,174
7	मौक ड्रील	75,500
8	भूकंप / अग्नि सुरक्षा	35,175
9	एस डी एम एफ	7,370
10	बिहार दिवस 2024	22,368
11	सोनपुर मेला 2022	8,037
12	हिंदी दिवस	10,137
13	इनसे मिलिए	17,200
14	वाहन क्रय	20,58,420
15	चिकित्सा	2,16,803
16	दूरभाष	4,048
C	**“अपस्केलींग ऑफ़ आपदा मित्र”**	1,43,21,607

(P) जन–जागरूकता के लिए मास मैसेजिंग

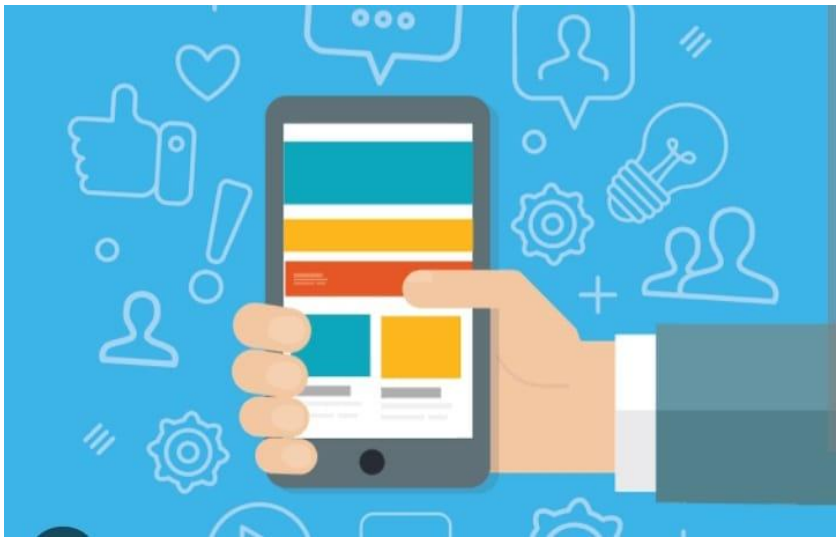

प्राकृतिक आपदाओं को हम पूरी तरह रोक तो नहीं सकते, परंतु बेहतर आपदा प्रबंधन एवं इसके सुदृढ़ीकरण से नुकसान को कम कर सकते हैं। इसके लिए आमलोगों को आपदा के खतरों से अवगत कराना जरूरी है। इसे ध्यान में रख प्राधिकरण की ओर से विभिन्न आपदाओं की स्थिति में 'क्या करें, क्या न करें' की जानकारी एसएमएस के माध्यम से लोगों को दी जाती है।

प्राधिकरण में जिला पदाधिकारी (38), एडीएम (38), बीडीओ (534), सीओ (534), प्रशिक्षित फोकल टीचर (1542), नाव एवं नाव मालिक (3820), पंचायत जनप्रतिनिधि (चयनित–207429, गैर चयनित–435699), जीविका दीदी– (148890), आशा कार्यकर्ता (77542) व आंगनबाड़ी सेविका (45946) के नंबर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित अभियंताओं एवं राजमिस्त्रियों के नंबर भी मौजूद हैं। इस तरह लगभग 36 लाख नंबर पर सामूहिक संदेश संप्रेषण (मास मैसेजिंग) नियमित रूप से किए जाते हैं। जनवरी, 2024 में कुल 2338868 मास मैसेजिंग किए गए। शीतलहर से बचाव और सड़क सुरक्षा से जुड़े संदेश इस माह में प्रसारित किए गए।